भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3073
(दिनांक 19.03.2025 को उत्तर के लिए)

आईआईएएस-डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025

3073. श्री शशांक मणि:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईआईएएस-डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 में 58 देशों की भागीदारी ने भारत में प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया;

(ख) सम्मेलन में किस प्रकार शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल रूपांतरण के एकीकरण पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सरकार प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अनुवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम या सहयोग शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है?

उत्तर

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ) : अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के सदस्य देश के रूप में, भारत ने 10 से 14 फरवरी, 2025 को "अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार: नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना" विषय पर आईआईएएस-डीएआरपीजी भारत सम्मेलन 2025 की मेजबानी की। भारत ने लोक प्रशासन में, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान सृजन और जानकारी के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए आईआईएएस प्रकाशन श्रृंखला के तहत "विकसित भारत@2047: शासन में बदलाव" शीर्षक से एक मौलिक पुस्तक प्रकाशित की। सम्मेलन में, 58 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों द्वारा, प्लेनरी/ब्रेकआउट सत्रों में 300 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। कई शोध पत्र, जिनमें भारतीय प्रतिनिधियों के पत्र भी शामिल थे, AI के माध्यम से शासन में डिजिटल परिवर्तन किए जाने पर केंद्रित थे। यह सम्मेलन, ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए एक, अकादमिक बहुपक्षीय मंच है।

****